GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CIVIL AVIATION
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO : 126
(TO BE ANSWERED ON THE 19th December 2022)

ACHIEVEMENT UNDER UDE DESH KA AAM NAGRIK (UDAN) SCHEME

*126. SMT MAMATA MOHANTA

Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:-

(a) whether Government has achieved the objectives for which Ude Desh Ka Aam Nagrik (UDAN) Scheme was launched and if so, the details thereof;
(b) if not, the reasons therefor;
(c) whether Government has set any target under UDAN scheme for the next five years; and
(d) if so, the details thereof and the steps taken by Government to achieve the target?

ANSWER

MINISTER OF CIVIL AVIATION

(Shri Jyotiraditya M. Scindia)

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

*****

STATEMENT IN RESPECT OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 126 REGARDING "UDE DESH KA AAM NAGRIK UDAN SCHEME" TO BE ANSWERED ON 19.12.2022.

(a) to (d): Ministry of Civil Aviation has launched Regional Connectivity Scheme (RCS) - UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik) on 21.10.2016 to stimulate regional air connectivity and making air travel affordable to the masses. As on 30.11.2022, after four rounds of bidding under UDAN, 453 routes have commenced, operationalizing 70 Airports including 2 Water Aerodrome & 9 Heliports. More than 2.15 lakh UDAN flights have operated and over 1.1 crore passengers have availed the benefits in UDAN flights so far. The scheme has been able to provide air connectivity to Tier-2 &Tier-3 cities at affordable airfares and has transformed the way people travel.

The UDAN Scheme is applicable for a period of 10 years from the date of notification of Scheme. The Government has set a target to operationalize 1000 UDAN routes during the currency of the scheme and to revive/develop 100 unserved & underserved airports/heliports/water aerodromes by 2024. The Government of India has approved a budget of Rs. 4500 crore for revival of existing unserved / underserved airports / airstrips of the State Governments, Airports Authority of India, Public Sector Undertakings and Civil Enclaves. Airports Authority of India (AAI), the Implementing Agency, monitors the progress for the revival/development of awarded aerodromes under UDAN and the same is reviewed by the Ministry in consultation with stakeholders time to time.

*****

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

राज्य सभा

मौखिक प्रश्न संख्या : **126**

सोमवार,19 दिसंबर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) योजना के तहत उपलब्धि

* **126. श्रीमती ममता मोहंता:**

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है जिनके लिए 'उड़े देश का आम नागरिक' (उड़ान) योजना शुरू की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;
(ग) क्या सरकार ने उड़ान योजना के तहत अगले पांच वर्षों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क)से (घ) तक: एक वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है।

"उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजनाके तहत उपलब्धि" के संबंध में राज्यसभा के दिनांक 19.12.2022 के तारांकित प्रश्न संख्या 126 के उत्तर में दिया गया वक्तव्य।

(क)से (घ): नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने और आम जनता के लिए हवाई यात्रा को वहनीय बनाने के उद्देश्य से दिनांक 21-10-2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) - उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की थी। 30.11.2022 तक, उड़ान योजना के तहत बोली के चार चरणों के बाद, 2 वॉटर ऐरोड्रोम्स और 9 हेलीपोर्ट्स सहित 70 हवाईअड्डों को जोड़ते हुए 453 मार्गों पर प्रचालन आरंभ किया जा चुका है। उड़ान योजना के अंतर्गत, 2.15 लाख से अधिक उड़ानों का प्रचालन किया जा चुका है और अब तक 1.1 करोड़ से अधिक यात्रियों ने उड़ान योजना के अंतर्गत प्रचालित उड़ानों का लाभ उठाया है। यह योजना, टियर-2 और टियर-3 शहरों को किफ़ायती हवाई किरायों पर संपर्क प्रदान कराने में सफल रही है और इस योजना ने, आम जनता का यात्रा करने का तरीका बदल दिया है।

उड़ान योजना,इसयोजना की अधिसूचना की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू है। सरकार ने योजना की अवधि के दौरान, 1000 उड़ान मार्गों को प्रचालित करने और 2024 तक 100 अपरिचालित तथा अल्प-परिचालित हवाईअड्डों अथवा हेलीपोर्ट्स या वॉटर ऐरोड्रोम्स का पुनरुद्धार करने अथवा इन्हें विकसित करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने, राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और सिविल एन्क्लेवों के मौजूदा अपरिचालित अथवा अल्प-परिचालित हवाईअड्डों या हवाई पट्टियों के पुनरुत्थान हेतु 4500 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दे दी है। कार्यान्वयन एजेंसी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा), उड़ान योजना के तहत अवार्ड किए गए हवाईअड्डों के पुनरुद्धार अथवा विकास हेतु किए गए कार्यों की निगरानी करता है और मंत्रालय द्वारा समय-समय पर स्टेकधारकों के परामर्श से इसकी समीक्षा की जाती है।

*****

श्रीमती ममता मोहंताः उपसभापति महोदय, आरसीएस-उड़ान चतुर्थ योजना के अधीन 2020 में देश के रिमोट और रीजनल स्थानों पर कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए 78 नए रूट्स का अनुमोदन किया गया था। सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि इस नए रूट में ओडिशा का कोई सेक्टर शामिल है या नहीं? यदि नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार कोई नया रूट प्रस्तुत कर रही है?

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधियाः सर, जहां तक ओडिशा की बात है, तो वर्तमान में we have 22 operationalized routes और हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में 16 ऐसे रूट्स हैं, जिनमें 14 रूट्स में हमारे दो एयरपोर्ट्स जल्दी तैयार होने वाले हैं और दो रूट्स एयरलाइन्स अभी चला नहीं पा रही है। हमारी कोशिश यह है कि आने वाली अवधि में भी उड़ान 4.2 के तहत हमने 184 रूट्स अधिक दिए हैं, जिनमें से करीब 16 हेलिकॉप्टर रूट्स हैं, 50 सीप्लेन रूट्स हैं और करीब 118 फ्रिक्स्ड विंग के रूट्स हैं। आने वाले समय में भी हम लोग ओडिशा को जरूर प्राथमिकता देंगे।

श्रीमती ममता मोहंताः महोदय, उड़ान योजना के अंतर्गत कितने एयरपोर्ट्स कवर हुए हैं? क्या इस योजना का और विस्तार करने की कोई योजना है? अगर है, तो किस राज्य के कितने ट्राइबल जिलों को इस योजना से लाभान्वित करेंगे?

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधियाः सर, उड़ान भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। प्रधान मंत्री जी की यह महत्वाकांक्षी योजना है कि उड़े देश का आम नागरिक। 2016 में इसकी शुरुआत हुई और इस योजना के तहत पिछले 6 वर्षों में करीब 2 लाख, 15 हज़ार नई फ्लाइट्स उड़ी हैं और इसके साथ 1 करोड़, 15 लाख लोग, जिन्होंने कभी भी प्लेन में सफर नहीं किया हो, केवल खेत में खड़े होकर प्लेन को देखा हो, ऐसे लोगों ने प्लेन में सफर किया है। देश के विकास और प्रगति में उड़ान योजना की यह महत्ता है और 11 एयरलाइन्स इसके भाग हैं, जिसमें से तीन नए स्टार्ट-अप्स भी हैं। महोदय, 70 नए एयरपोर्ट बने हैं - ऐसी-ऐसी जगहों पर जहां द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पूर्ण रूप से एयरपोर्ट मिटाए गए थे, वहां एयरपोर्ट्स स्थापित हुए हैं। चाहे वह दरभंगा हो, रूपसी हो या किशनगढ़ हो, ऐसे अनेक स्थान हैं, जहां ढाई लाख से साढ़े तीन लाख यात्री प्रति वर्ष उन एयरपोर्ट्स से सफर कर रहे हैं। आने वाले सालों में, जो 70 एयरपोर्ट्स हमारे बने हैं, उनके अतिरिक्त हम 2024 के अंत तक 68 नए एयरपोर्ट्स बनाने जा रहे हैं, ताकि नागर विमानन क्षेत्र विस्तृत बने और उसमें और गहराई आए।

श्रीमती रजनी अशोकराव पाटिलः सर, उड़ान स्कीम के संबंध में मंत्री महोदय ने जानकारी दी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में जहां पर ऑलरेडी एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र का नांदेड़ है, वहां पर विगत दो-तीन सालों से हवाई सेवा चालू नहीं है। जहां पर गवर्नमेंट की लागत लगी है, पैसा लगा है, वह तो बंद है और हम नए शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसके लिए सरकार कुछ करेगी?

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधियाः सर, नांदेड़ में हमने फ्लाइट कनेक्टिविटी की शुरुआत की थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि एयरलाइन ने वह रूट बंद कर दिया है। इसको लेकर हमारी कोशिश है और आने वाले उड़ान 5.0 में भी हम नांदेड़ को प्राथमिकता जरूर देंगे, क्योंकि नांदेड़ केवल महाराष्ट्र की दृष्टि से ही एक ऐतिहासिक स्थान नहीं है, बल्कि राष्ट्र के दृष्टिकोण से हमारे सिख समाज के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि हम इसे प्राथमिकता जरूर देंगे।

श्रीमती कान्ता कर्दमः सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी पूछना चाहती हूं कि क्या इस योजना के तहत चालू हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि हुई है तथा उड़ान के तहत प्रचालित आरसीएस मार्गों और हवाई अड्डों का उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार विवरण क्या है?

श्री उपसभापतिः कान्ता जी, आपने एक सवाल पूछ लिया है। आपका एक सवाल हो गया है।

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधियाः उपसभापति महोदय, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। हमारे भारतवर्ष में 2013-14 तक केवल 74 हवाई अड्डे स्थापित थे और इन 8 वर्षों में प्रधान मंत्री जी की प्राथमिकता के आधार पर आज 71 नए हवाई अड्डे, वाटर एयरोड्रोम और सीड्रोम स्थापित हो गए हैं, जिनकी संख्या 145 है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 5-6 सालों में 74 से 145 तक जो हमारा सफर रहा है, यह जारी रहेगा और हम लोग 200 का आंकड़ा पार करेंगे। इसी के साथ जहां तक हम लोगों के प्लेन के फ्लीट की बात है, वह 2013-14 में केवल 400 तक सीमित थी। आज वह 700 पर आ गई है और हर वर्ष 100 से 125 प्लेन्स का एक्विज़िशन होगा और आने वाले पाँच साल के अंदर हम 1,200 के आंकड़े को भी पार करेंगे, यह हमें विश्वास है।

श्री उपसभापतिः माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी।

श्री इमरान प्रतापगढ़ीः उपसभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न है कि सरकार का नारा था कि चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज से सफर करेगा। ... **(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्यः हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज से सफर करेगा ... **(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः आप इमरान जी को सवाल पूछने दीजिए।

श्री इमरान प्रतापगढ़ीः सर, हर चीज़ पर टीका-टिप्पणी करना अच्छा नहीं है। सर, आप उनको भी मना कीजिए।

श्री उपसभापतिः मैं सबको मना कर रहा हूं।

श्री इमरान प्रतापगढ़ीः सर, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी थोड़ा-सा यात्रा का अनुपात बढ़ता है, टिकट इतने ज्यादा महंगे हो जाते हैं कि उन पर कोई कंट्रोल नहीं रह जाता है। सर, पांच हजार का टिकट बीस-बीस हजार, पच्चीस-पच्चीस हजार में बिकता है। क्या माननीय मंत्री जी के पास प्राइवेट एयरलाइन्स के बढ़ते हुए टिकटों के रेट को कंट्रोल करने का कोई उपाय है, जिससे कि टिकट सस्ता रह सके और आम यात्री हवाई जहाज से यात्रा कर सके?

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधियाः सर, मैं आपके माध्यम से सांसद महोदय को सूचित करना चाहूंगा कि शायद इनके वायर्स क्रॉस हो गये हैं, ये UDAN योजना और साधारण टिकटों के आधार पर मिक्स-अप कर रहे हैं। सर, UDAN योजना के तहत वायबिलिटी गैप फंडिंग मैकेनिज़्म के तहत सस्ते टिकट दिए जाते हैं, ताकि उस रूट को हम लोग वायेबल कर पायें। सर, उसी के आधार पर एक करोड़, दस लाख लोग इस देश में हवाई सफर कर पाये हैं, जिन्होंने कभी भी कल्पना नहीं की थी। जहां तवज्जो दी जानी चाहिए, उसके लिए मैं सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्हें वहां पर तवज्जो देनी चाहिए।

जहां तक उन्होंने विषय उठाया है कि टिकट के दाम बढ़े हैं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। इसका विस्तृत उत्तर मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में दिया है। मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हमारे सेक्टर में प्राथमिकता से दो फैक्टर होते हैं। एक सीज़नैलिटी का फैक्टर होता है, जिसमें एक लीन सीज़न होता है, जहां टिकट के दाम कम होते हैं और एक हाई सीज़न होता है, जहां टिकट के दाम बढ़ जाते हैं। ऐसा केवल भारत में ही नहीं है। यह स्थिति विश्व स्तर पर होती है। आज हम लोग हाई सीज़न में चल रहे हैं, नम्बर एक। नम्बर दो, टिकट के डेज़िग्नेटिड बकेट्स होते हैं, अगर हम लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, तो उसके लिए एडवांस में बुकिंग करेंगे, तो आपको लोएस्ट फेयर से भी दो-तीन हजार रुपये कम का टिकट मिलेगा, लेकिन अगर आखिरी दिन पर हम लोग टिकट बुक करेंगे, तो उसका फेयर जरूर बढ़ जाता है। सर, मैंने तीसरा मुद्दा आपके समक्ष रखा था कि एयर टर्बाइन फ्यूल की कॉस्ट अंतरराष्ट्रीय जगत में, जो प्री-कोविड 53,000 रुपए प्रति किलो-लीटर था, वह अब वर्तमान समय में 1,17,000 रुपए प्रति किलो-लीटर हो चुका है, जो 50 प्रतिशत की इनपुट कॉस्ट एयरलाइन्स की होती है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Question No. 127; Shri S. Kalyanasundaram.